बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 224 ● नई दिल्ली ● शनिवार 06 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

डीयू शिक्षक संघ चुनाव में लहराया भगवा परचम, भाजपा समर्थित एनडीटीएफ के प्रो. नेगी बने अध्यक्ष

दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव में भगवा परचम लहराया है। भाजपा समर्थित शिक्षक संगठन एनडीटीएफ के प्रो वीएस नेगी डूटा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने वामपंथी संगठन डीटीएफ के प्रो राजीव रे को 638 मतों से हराया। बीते साल भी एनडीटीएफ ने डूटा अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। तब प्रो ए.के भागी अध्यक्ष बने थे। रात दो से तीन बजे के बीच घोषित किये गए थे नतीजे। प्रो को 3766 वोट मिले जबकि राजीव रे को 2728 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन एएडीटीए के राजेश झा को 1451 मत मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान उत्साहपूर्ण रहा, जिसमें 9,800 पात्र शिक्षकों में से 8,221 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

लश्कर-ए-जिहादी की मुंबई को दहलाने की धमकी, 34 मानव बम, 400 किलो आरडीएक्स का दावा

मुंबई।

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक धमकी भरा कॉल आने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि 34 गाड़ियों में 34 मानव बम रखे गए हैं, जिनमें 400 किलोग्राम आरडीएक्स है। ये बम विस्फोट पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे। यह धमकी भरा कॉल ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर आया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर लश्कर-ए-जिहादी नामक संगठन ने यह धमकी जारी की थी। पुलिस ने बताया कि पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरे संदेश में दावा किया गया है कि मानव बमों से लदी 34 कारों का इस्तेमाल 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोट करने के लिए किया जाएगा, जिससे एक करोड़ लोग मारे जाएँगे। वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक रेलवे स्टेशन को उड़ाने की झूठी धमकी देने के आरोप में सोमवार को एक 43 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान रूपेश मधुकर रणपिसे के रूप में हुई है, ने रविवार शाम करीब 4 बजे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने कलवा रेलवे स्टेशन पर बम रखा है। अगस्त में, दक्षिण मुंबई के गिरगाँव इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला था, जो परिसर की गहन तलाशी के बाद फर्जी निकला। एक अधिकारी ने बताया कि 22 अगस्त की शाम को मंदिर प्रशासन को एक आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम विस्फोट की चेतावनी वाला एक ईमेल मिला। अधिकारी ने बताया कि मंदिर के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद रात में बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) के साथ परिसर की तलाशी ली गई।

निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करे सरकार, कांग्रेस बोली- शीतकालीन सत्र में लाया जाए कानून

नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को मोदी सरकार से मांग की कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून लाया जाए। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। कांग्रेस ने दावा किया कि इन वर्गों के छात्र निजी विश्वविद्यालयों में बेहद कम संख्या में मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में निजी शिक्षा संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक तंगी और आरक्षण लागू न होने की वजह से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे इन संस्थानों में पढ़ाई का अवसर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यूपीए सरकार ने आरक्षण का कानून बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008, 2011 और 2014 में वैध ठहराया। कांग्रेस ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि निजी शिक्षा संस्थानों में केवल 0.89 फीसदी एससी,0.53 फीसदी एसटी और 11.16 फीसदी ओबीसी छात्र हैं। आदिवासी कांग्रेस प्रमुख विक्रांत भूरिया ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए वोट का अधिकार और आरक्षण दोनों को जरूरी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर मोदी सरकार ने 11 साल से कोई कदम नहीं उठाया है। ओबीसी विभाग प्रमुख अनिल जयहिंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक मोदी सरकार 'क्रीमी लेयर' की समीक्षा तक नहीं कर पाई। कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' में निजी शिक्षा संस्थानों में अनुच्छेद 15(5) लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अब संसद की स्थायी समिति ने भी सर्वसम्मति से इस कानून को लागू करने की सिफारिश की है। कांग्रेस ने मांग की कि मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में यह कानून लेकर आए।

अब प्रधानमंत्री पद से जाने का समय हो गया है- संजय राउत

मुंबई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने मणिपुर का दौरा कर सकते हैं. वहां हुई हिंसा के बाद पीएम का ये पहला दौरा होने वाला है. इस पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मणिपुर जा रहे है तो बड़ी बात है क्या, प्रधानमंत्री है, दो तीन साल के बाद जा रहे है. जब मणिपुर जल रहा था, हिंसा भड़क रही थी तब जाने की हिम्मत नहीं की. अब प्रधानमंत्री पद से मोदी जी के जाने का समय हो गया है तो वहां पर्यटन करने जा रहे हैं. बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा का मामला संसद में भी उठा था. विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है.

13 सितंबर को मणिपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी- अधिकारी

आइजोल में अधिकारियों के अनुसार, पीएम मोदी मिजोरम का दौरा करने के बाद 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचेंगे, जहां वह रेलवे की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे. हालांकि, नई दिल्ली या इंफाल से इस यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बीजेपी की मणिपुर इकाई ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

चुराचांदपुर जिला ड्रोन निषिद्ध क्षेत्र

इस बीच मणिपुर के चुराचांदपुर जिले को ड्रोन निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है. जिलाधिकारी धरुण कुमार एस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, वीवीआईपी (अति महत्वपूर्ण व्यक्ति) के दौरे के दौरान सुरक्षा कड़ी करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा, यमुना का जलस्तर कम होने के संकेत

नई दिल्ली । दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शुक्रवार सुबह सात बजे 207.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 207.48 मीटर पर था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सुबह छह बजे जलस्तर 207.35 मीटर पर था। अधिकारियों के अनुसार, आज जलस्तर और कम होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में नदी ने निचले इलाकों में कहर बरपाया है, जिससे कई मकानों में पानी भर गया, लोग विस्थापित हुए हैं और व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जबकि बृहस्पतिवार को यमुना नदी का पानी सिविल लाइंस इलाके में घुस गया। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल (लोहा पुल) पर यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 207.47 मीटर पर पहुंच गया। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आनी शुरू हो गई है। यमुना नदी का जलस्तर शाम सात बजे तक 207.42 मीटर दर्ज किया गया। बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान में कहा गया है कि शुक्रवार सुबह आठ बजे तक जलस्तर 207.30 मीटर तक गिर जाएगा।

मयूर विहार फेज-1 और यमुना बाजार में बाढ़ का पानी राहत शिविरों में घुस गया, जिससे सैलाब के कारण विस्थापित हुए लोगों की परेशानी और बढ़ गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उस्मानपुर के तीसरे पुश्ते पर कुछ लोग, पालतू जानवर और एक गाय फंस गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने बचाव कार्य करने से इनकार कर दिया, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और बोट क्लब के कर्मचारियों ने सभी गायों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोहा पुल के पास एक गौशाला से गायों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर, दक्षिण पूर्व और शाहदरा जिलों में स्थिति स्थिर बनी हुई है। मध्य दिल्ली में, डीडीएमए और बोट क्लब द्वारा 9 अपर बेला रोड से चार लोगों को निकाला गया, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक थी। सिविल लाइंस क्षेत्र में सड़कें नालों में बदल गईं, क्योंकि यदि पानी में घर डूब गए। इस क्षेत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जब भी यमुना खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर प्रवाहित होती है, तब यही स्थिति सामने आती है। उन्होंने अधिकारियों पर उचित तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया। मजनू का टीला में हुए नुकसान ने हर तरह के व्यवसाय को प्रभावित किया है। कई रेस्तरां के मालिक अब अपने कार्यालयों में सोते हैं, टैटू पार्लरों की मशीनें बर्बाद हो गई हैं, सैलून और स्पा के उपकरण काम नहीं कर रहे हैं तथा कपड़ों की दुकानें पानी जमा होने के कारण बंद पड़ी हैं। सिविल लाइंस के पास चंदगी राम अखाड़े में भी पानी भर गया, जिसके कारण दिल्ली यातायात पुलिस को वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने का आदेश देना पड़ा।

जलभराव का कारण इलाके में खराब निकासी की स्थिति

अधिकारियों ने इस जलभराव का कारण इलाके में खराब निकासी की स्थिति को बताया। दिल्ली सचिवालय भी जलमग्न हो गया। वासुदेव घाट के आस-पास के इलाके भी जलमग्न हो गए। मयूर विहार फेज 1 जैसे निचले इलाकों में कुछ राहत शिविर जलमग्न हो गए, जिसके कारण विपक्ष ने सरकार के इंतजामों की आलोचना की।

शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का अनूठा संगम 5 सितंबर 2025- भारतीय संस्कृति और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक

वैश्विक स्तरपर भारत विविधताओं का देश है जहाँ भाषाएँ, धर्म, संस्कृतियाँ,परंपराएँ और विचारधाराएँ एक साथ मिलकर सह-अस्तित्व का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं।5सितंबर 2025 का दिन इस सांस्कृतिक विविधता को और भी गहराई से महसूस करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलादउन -नबी दोनों एक साथ मनाए जा रहे हैं। यह केवल कैलेंडर का संयोग भर नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के उस ताने-बाने का प्रमाण है जिसमें विभिन्न आस्थाएँ और मान्यताएँ एक ही मंच पर आकर सामंजस्य और भाईचारे का संदेश देती हैं। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र अपनी राइस सिटी के नाम से मशहूर गोंदिया सिटी में जब एक ही दिन आने वाले हैं दोनों पर्वों की तैयारी स्थलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोची।भारत के इतिहास में कई ऐसे अवसर आते रहे हैं जब अलग-अलग समुदायों के पर्व एक ही दिन पड़े हों। इसने हमेशा भारतीय लोकतंत्र और समाज की बहुलतावादी संरचना को मजबूत किया है। 5 सितंबर 2025 का यह संगम भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। जहाँ एक ओर शिक्षा और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करने वाला शिक्षक दिवस है,वहीं दूसरी ओर करुणा, नैतिकता और पैगम्बर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं को स्मरण कराने वाला ईद-ए-मिलाद-उन- नबी है। यह दो अलग-अलग आयामों के उत्सव हैं,किंतु दोनों ही मानवता के कल्याण और समाज के उत्थान से जुड़े हैं। साथियों बात अगर हम शिक्षक दिवस व ईद-ए-मिलाद- उन-नबी का निर्धारण और महत्व की करें तो,शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का साधन न मानकर, बल्कि जीवन और समाज को सही दिशा देने वाला स्तंभ बताया।उनकेअनुसार शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता होता है।1962 से हर वर्ष यह दिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह परंपरा शिक्षा और ज्ञान की महत्ता को रेखांकित करती है और समाज में गुरु-शिष्य परंपरा की गरिमा को बनाए रखती है।दूसरी ओर, ईद-ए-मिलाद-उन- नबी इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार तय होता है। इसे पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय पैगम्बर की शिक्षाओं, उनके जीवन-दर्शन और मानवता के लिए दिए गए मार्गदर्शन को याद करता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि इंसानियत, बराबरी और करुणा का संदेश भी देता है। चूंकि यह पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए हर वर्ष इसकी तिथि बदलती रहती है।संयोगवश 2025 में यह 5 सितंबर को पड़ रहा है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। साथियों बात अगर हम दोनों दोनों पर्वों के संयोग के ऐतिहासिक पहलू की करें तो, इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार, संभवतः पहली बार ऐसा अवसर आया है जब भारत का शिक्षक दिवस और इस्लामी जगत का ईद-ए- मिलाद-उन-नबी एक ही दिन मनाया जा रहा है। यह अद्वितीय संयोग भारत की सांस्कृतिक धरती की विशेषता को दर्शाता है। भारतीय समाज हमेशा से विभिन्न समुदायों के मेल-जोल का प्रतीक रहा है, और यह घटना उसी परंपरा की एक नई झलक प्रस्तुत करती है। साथियों बातें अगर हम दोनों पर्वों शिक्षा और धर्म के साझा संदेश की करें और इसे यदि हम गहराई से देखें तो शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद दोनों का मूल संदेश एक ही है, ज्ञान, नैतिकता और मानवता की सेवा। डॉ. राधाकृष्णन ने शिक्षा को राष्ट्र और मानवता के विकास की आधारशिला माना, वहीं पैगम्बर मुहम्मद साहब ने इंसानियत, भाईचारे और समानता को सबसे महत्वपूर्ण बताया। इस तरह, दोनों पर्व हमें सिखाते हैं कि चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या धर्म के माध्यम से, लक्ष्य हमेशा इंसान को बेहतर बनाना और समाज में शांति व न्याय स्थापित करना जरूरी है। साथियों बातें कर हमअंतरराष्ट्रीय स्तरपर यह संगम और भी महत्वपूर्ण है होने की करें तो, आज पूरी दुनियाँ धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक टकराव और सांस्कृतिक विभाजन की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत से यह संदेश जाता है कि विभिन्न धर्म और परंपराएँ एक साथ मिलकर मनाई जा सकती हैं और समाज में भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। यह केवल भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में भी एक प्रेरक उदाहरण है।शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का साझा उत्सव व सामाजिक प्रयोग है भारत के कई राज्यों में 5 सितंबर 2025 को विद्यालयों, कॉलेजों और मस्जिदों दोनों में उत्सव का माहौल रहेगा।

बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और मुस्लिम समाज पैगम्बर साहब की शिक्षाओं को याद करेगा। यह दृश्य उस सामाजिक प्रयोग जैसा होगा जहाँ दो अलग- अलग मान्यताएँ एक-दूसरे के साथ विरोध में नहीं, बल्कि सहयोग में खड़ी होती हैं। इससे समाज में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है। साथियों बात अगर हम अवकाश का प्रश्न,राष्ट्रीय और राजपत्रित छुट्टियाँ बहुसांस्कृतिकता का जीवंत उदाहरण की करें तो, ध्यानद्व देने योग्य तथ्य यह है कि न तो शिक्षक दिवस और न ही ईद-ए-मिलाद भारत में राष्ट्रीय अवकाश की श्रेणी में आते हैं। हालाँकि ईद-ए-मिलाद को राजपत्रित अवकाश माना जाता है, यानी केंद्र सरकार इसेमान्यता देती है और राज्यों को यह अधिकार होता है कि वे अपने स्तर पर छुट्टी घोषित करें। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में यह दिन सरकारी अवकाश होता है। इसके विपरीत, शिक्षक दिवस को प्रायः शैक्षिक संस्थानों में ही विशेष कार्यक्रमों और समारोहों के रूप में मनाया जाता है, जबकि औपचारिक अवकाश नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान और प्रशासन दोनों ही विभिन्न आस्थाओं को सम्मान देते हुए लचीलेपन की नीति अपनाते हैं।भारत की शक्ति हमेशा उसकी बहुसांस्कृतिकता में रही है। यहाँ एक ओर हिन्दू पर्व दीपावली और होली है, तो दूसरी ओर मुस्लिम पर्व ईद और मुहर्रम है,एक ओर क्रिसमस और गुड फ्राइडे है तो दूसरी ओर गुरु नानक जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। इन सभी त्योहारों का एक साथ मनाया जाना और समाज के हर वर्ग का इसमें शामिल होना ही भारत को विशिष्ट बनाता है।

शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का संगम इसी बहुसांस्कृतिक परंपरा की पुष्टि करता है जो अच्छी बात है। साथियों बात अगर हम वैश्विक शांति और शिक्षा का सेतु व भारतीय लोकतंत्र का संदेश की करें तो,आज कीदुनियाँ में जहाँ हिंसा, युद्ध और आतंकवाद जैसी चुनौतियाँ हैं,वहाँ शिक्षा और धार्मिक मूल्यों का सही संगम ही मानवता को बचा सकता है।शिक्षक दिवस शिक्षा के महत्व को उजागर करता है,जबकि ईद- ए- मिलाद हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। यदि इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह मानव सभ्यता के लिए एक मजबूत सेतु का काम करता है।भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। यहाँ न तो किसी एक धर्म को सर्वोपरि माना गया है और न ही किसी आस्था के अनुयायियों कोकमतर आँका गया है। 5 सितंबर 2025 का यह संयोग भारतीय लोकतंत्र के उस मूलभूत सिद्धांत को और मजबूत करता है,जिसमें सभी धर्म और मान्यताएँ समान रूप से आदरणीय हैं। यह दुनिया को यह संदेश देता है किलोकतंत्र केवल चुनाव या शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह विविधताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता भी है।दोनों पर्वों के संगम से समाज में सामूहिक उत्साह का वातावरण बनेगा। विद्यालयों और मस्जिदों से निकलने वाले संदेश मिलकर समाज में भाईचारे और शांति को और गहरा करेंगे। यह अवसर केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 5 सितंबर 2025 को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का संगम भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की जीवंत मिसाल है।यह केवल तिथियों का मेल नहीं, बल्कि शिक्षा और धर्म के साझा मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी समुदाय से आते हों, हमारे लक्ष्य और मूल्य समान हैंज्ञान, नैतिकता, इंसानियत और समाज का कल्याण। यह अद्वितीय अवसर भारत की उस आत्मा को प्रकट करता है, जो सदैव विविधताओं में एकता और विभिन्नताओं में सामंजस्य का मार्ग दिखाती है।

सम्पादकीय...

शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सफीना हुसैन के एनजीओ यानी नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन 'एजुकेट गर्ल्स' को 2025 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड

भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सफीना हुसैन के एनजीओ यानी नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन 'एजुकेट गर्ल्स' को 2025 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिलेगा। यह पहला इंडियन ऑर्गनाइजेशन है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय गैर-सरकारी संस्था है। यह संस्था दूरदराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। साल 2007 में सफीना हुसैन ने इसकी शुरुआत की थी। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 'एजुकेट गर्ल्स' मैग्सेसे सम्मान पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ है। सफीना हुसैन का जन्म 1971 में दिल्ली में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। गरीबी,घरेलू हिंसा और मुश्किल हालातों ने उनके रास्ते में कई रुकावटें खड़ी कीं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। परिवार चाहता था कि उनकी जल्दी शादी कर दी जाए लेकिन एक रिश्तेदार आंटी ने उनका साथ दिया। उन्हें अपने घर में जगह दी और पढ़ाई दोबारा शुरू करने में मदद की। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सफीना ने 1987 से 1989 तक दिल्ली के डीपीएस स्कूल आरके पुरम से पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद सफीना ने पारंपरिक रास्ता अपनाया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि, ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला और मात्र 9 महीने में नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने कम्युनिटी-बेस्ड ग्लोबल डेवलपमेंट सेक्टर में अपना करियर शुरू किया। इसके चलते उन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की यात्राएं कीं। सफीना ने दो साल तक गर्ल्स एजुकेशन की समस्या का अध्ययन किया और उसके बाद साल 2007 में 'एजुकेट गर्ल्स' नाम के एनजीओ की शुरुआत की। यह एनजीओ ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियों की पहचान करता है और उन्हें स्कूलों में भर्ती करवाता है। जब उन्होंने 50 स्कूलों से अपने काम की शुरुआत की तब उन्हें कोई फंड कहीं से नहीं मिला। उन्होंने अपने खर्चे से काम शुरू किया लेकिन जब रिजल्ट्स दिखने लगे तो राजस्थान सरकार ने 500 स्कूलों में काम करने की परमिशन दी और 5 प्रतिशत का सपोर्ट दिया। फिर जब सरकार ने एक पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने की परमिशन दी तो 17 प्रतिशत का सपोर्ट दिया। यानी जैसे-जैसे गवर्नमेंट का भरोसा बढ़ता गया उनका सपोर्ट भी बढ़ता गया। एजुकेट गर्ल्स को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इस संस्था ने उन परंपरागत सोच और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी जिनकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई पर रोक लगाई जाती थी। संस्था ने हजारों बच्चियों को निरक्षरता से बाहर निकाल कर शिक्षा, हिम्मत, हुनर और आत्मनिर्भरता की ताकत दी। इस अवॉर्ड के साथ एजुकेट गर्ल्स अब उन महान हस्तियों की पंक्ति में शामिल हो गई है जिनमें सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर टेरेसा और हायाओ मियाजाकी जैसे नाम आते हैं। -हमारे लिए शिक्षा सिर्फ प्रगति का रास्ता नहीं बल्कि हर लड़की का बुनियादी अधिकार है। यह सम्मान साबित करता है कि अगर सरकार, कॉर्पोरेट और समाज साथ आएं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को बदला जा सकता है। हम भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मिशन को मजबूत बनाया।- यह बात सच है कि आज के आधुनिक दौर में भी हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवादी सोच पल रही है जो लड़कियों की शिक्षा को तवज्जो देने से रोकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस धारणा की बेड़ियों को तोड़कर लड़कियों को निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकालने और उनका शिक्षा के उजाले से साक्षात्कार कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। 'एजुकेट गर्ल्स' संस्था ने इस तरह के सफल प्रयासों की एक नई मिसाल पेश की है। इस संस्था ने राजस्थान से शुरुआत करते हुए देशभर में सबसे जरूरतमंद समुदायों की पहचान की, स्कूल न जाने वाली लाखों लड़कियों को कक्षा में पहुंचाया और उन्हें उच्च शिक्षा एवं रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाया। एजुकेट गर्ल्स ने अब तक 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाया है। एजुकेट गर्ल्स की इस पहल से 1.55 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। खास बात यह है कि वे सिर्फ स्कूल में दाखिला कराने तक नहीं रुकते। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चियां स्कूल में टिकें और पढ़ाई में बेहतर करें। इसके लिए वे टीम बालिका नाम से 55,000 वॉलेंटियर्स की टीम के साथ काम करते हैं। ये वॉलेंटियर्स गांव-गांव जाकर उन परिवारों को समझाते हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में हिचकते हैं। संगठन ने प्रगति नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया जिसके तहत 15 से 29 साल की 31,500 युवतियों को ओपन स्कूलिंग के जरिए पढ़ाई पूरी करने में मदद की जाती है। इसके अलावा 2015 में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड शुरू किया गया जिसने राजस्थान में दाखिला और पढ़ाई के नतीजों को बेहतर किया। सफीना की शादी मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता से हुई है जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं। उनके पिता यूसुफ हुसैन बॉलीवुड अभिनेता थे, जिनका 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। सफीना की कहानी और उनका काम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह कहती हैं कि एक लड़की को पढ़ाने का असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को बदल देता है। उनका लक्ष्य है कि 2035 तक 1 करोड़ बच्चों तक उनकी पहुंच हो और उनका मॉडल दुनियाभर में अपनाया जाए।

नेक्सट जेन जीएसटी सुधार

लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव लाने की जो घोषणा की थी उसे पूरा कर दिया गया है। वर्ष 2017 से लागू की गई वस्तु एवं कर सेवा को आसान बनाने की प्रक्रिया के तहत जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब में से 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे तथा 5 और 18 प्रतिशत वाले स्लैब ही रहेंगे। नुकसानदेह और विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर से शुल्क लगाने का फैसला किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं इस टू टियर टैक्स स्ट्रक्चर से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार करने में बहुत आसानी होगी। आम आदमी ने तो सस्ती और महंगे होने वाले उत्पादों के बारे में तो जानकारी ले ही ली होगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हर कोई जेब के मुताबिक बाजार में जाकर खरीदारी करेगा। भारत निर्यात उन्मुखी देश नहीं है। हम जो पैदा करते हैं उसी को अपने ही बाजार में बेचते हैं। अगर बाजार में चीजें सस्ती होती है तो निश्चय ही इससे आम आदमी को राहत मिलती है। बाजार तभी गुलजार होंगे जब उपभोक्ता की जेब में पैसा होगा। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ही हर साल सरकार की कमाई में जोरदार इजाफा होता आया है। इस साल 2025 में तो जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। शुरूआती साल में इसके जरिए सरकारी खजाने में 7.41 लाख करोड़ रुपये (जुलाई से मार्च तक) आए थे, तो वहीं अगले साल 2018-19 में जीएसटी से कमाई का आंकड़ा 11.77 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं इसकी शुरुआत से अब तक कलेक्शन में तीन गुना से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है और 2021-22 से लेकर 2024-25 तक सिर्फ पांच साल में ही जीएसटी से सरकार की कमाई दोगुनी हो चुकी है और ये 11.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इस साल 2025 में जीएसटी क्लैक्शन ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े और सरकार की ताबड़तोड़ कमाई कराई। अप्रैल महीने में अब तक सबसे बड़ा मासिक जीएसटी क्लैक्शन हुआ जो 2.37 लाख करोड़ का रहा। जीएसटी दरों में बदलाव के चलते सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ के सालाना राजस्व नुकसान की आशंका जताई है। इसका मतलब यह है कि कर सुधारों से कमाई पर असर पड़ेगा। विपक्ष शासित राज्य सरकारें राजस्व की भरपाई की मांग कर रही हैं। राज्यों का कहना है कि अगर वर्ष 24-25 के आधार वर्ष होने के कारण वृद्धि 14 फीसदी से कम रहती है तो?उनके राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। विशेषज्ञ लम्बे समय से यह कहते रहे हैं कि अलग-अलग स्लैब होने से जीएसटी प्रणाली का कामकाज और प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्हें युक्ति संगत बनाने की कवायद काफी समय से लम्बित थी। जीएसटी के शुरूआती पांच साल तक राज्यों की क्षतिपूर्ति उपकर के जरिये की गई।

कोरोना महामारी के दौरान जब उपकर संग्रह कम हो गया तो उसकी भरपाई उधारी से की गई। फिर उधारी को चुकाने के लिए उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई गई लेकिन यह व्यवस्था हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। राज्यों को राजस्व की हानि न हो। इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि स्लैब कम होने से घरेलू मांग में जबरदस्त इजाफा होगा और इससे राजस्व बढ़ेगा।

अगर राजस्व संग्रह बेहतर होता है तो फिर राज्यों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कर सुधारों से उद्योग जगत को भी फायदा होगा। कपड़ा, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल उद्योग को इस फैसले से लाभ होगा क्योंकि कर घटने से उनकी बिक्री बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, 1,200 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मध्यमवर्गीय खरीदारों के लिए सकारात्मक रहेगा और इससे ऑटोमोबाइल सैक्टर की बिक्री में उछाल आ सकता है। वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें घटने से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर लग्जरी गाड़ियां और महंगे इलैक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि 40 प्रतिशत कर से उनकी बिक्री घट सकती है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए किए गए सुधार भी महत्वपूर्ण हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर देना और निर्यातकों को ऑटोमैटिक रिफंड की सुविधा देना व्यापार को आसानी को बढ़ाएगा। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों की नकदी प्रवाह में सुधार होगा और वे अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा पाएंगे। ऑटोमैटिक रिटर्न फाइलिंग का नया प्रस्ताव जीएसटी अनुपालन को सरल बनाएगा और करदाताओं को झंझट से बचाएगा। यह सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में एक अहम कदम माना जाएगा। जीएसटी परिषद ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। अर्थशा?स्त्रियों का अनुमान है कि इससे आर्थिक विकास होगा तथा अमरीकी टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। इन कर सुधारों को नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार कहा गया है। उम्मीद की जाती है कि इन बदलावों से भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य राजस्व के लिए जीएसटी पर ही निर्भर हैं। राज्यों के साथ राजस्व साझा करने के मामले पर केन्द्र को उदार हृदय से काम लेना होगा।

शिक्षा को केवल करियर निर्माण का साधन न मानकर जीवन निर्माण का आधार : प्रो. वंशीधर पांडेय

डॉ. घनश्याम सिंह महाविद्यालय, आगरा के बहुउद्देशीय सभागार में कला एवं मानविकी संकाय,भाषा संकाय तथा ललित कला संकाय के संयुक्त तत्वावधान में नवप्रवेशित बी.ए. एवं बी.एफ.ए. प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक संरचना, पाठ्यचर्या, संस्थागत मूल्यों एवं भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं महाविद्यालय के प्रेरणास्रोत डॉ. घनश्याम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात् प्रख्यात समाजविज्ञानी प्रो. वंशीधर पांडेय ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने शिक्षा को केवल करियर निर्माण का साधन न मानकर जीवन निर्माण का आधार बताते हुए विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, समर्पण एवं सृजनशीलता अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रो. पांडेय ने विशेष रूप से बी.ए. एवं बी.एफ.ए. जैसे पाठ्यक्रमों की सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमताओं एवं मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। महाविद्यालय प्रबंधक श्री नागेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक संसाधनों का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। स्वागत भाषण हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. गौरव तिवारी ने दिया। तत्पश्चात् डॉ. विवेकानंद चौबे ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की संरचना, विषय चयन की प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी शैक्षणिक सावधानियों से अवगत कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आनंद सिंह ने अपने उद्बोधन में संस्थान की शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुसंधानपरक दृष्टि, सतत विकास की अवधारणा तथा पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक शैक्षणिक नवाचारों के संतुलन पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को संस्थान के नियमों, संसाधनों तथा उपलब्ध अवसरों के प्रति सजग रहने और उन्हें आत्म-विकास के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंकिता यादव ने किया तथा श्री अरविंद चौबे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण–डॉ. डी. वी. सिंह, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. विपुल कुमार शुक्ला, डॉ. रचना पांडेय, डॉ. विनीत सिंह, डॉ. अभिषेक गुप्ता, श्री कुलदीप यादव, डॉ. संदीप राय, सुश्री खुशबू सिंह, श्रीमती रितु सिंह, प्रीति शाह, डॉ. मुकेश विश्वकर्मा, डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. धर्मराज यादव, डॉ. रितेश सिंह आदि की सक्रिय उपस्थिति रही।

डोनाल्ड ट्रम्प को गुस्सा क्यों आता है?

भारत और अमेरिका के रिश्ते लड़खड़ा रहे हैं। अगर जल्द न रोका गया तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि मरम्मत की गुंजाइश नहीं रहेगी और जब तक ट्रम्प व्हाइट हाउस छोड़ेंगे तब तक इन रिश्तों का कुछ नहीं बचेगा। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25फीसदी टैरिफ (कुल 50फीसदी) लगा दिया गया है जबकि चीन जो हमसे भी अधिक खरीदता है पर 30 फीसदी टैरिफ है। कूटनीतिक शालीनता को एक तरफ रख न केवल ट्रम्प बल्कि उनके कई सलाहकार रोजाना हमें लताड़ रहे हैं। एक कथित सलाहकार पीटर नावरो का कहना है कि यूक्रेन का युद्ध 'मोदी का युद्ध है' ! फिर कहना था कि रूस से तेल खरीद से भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। भारत-अमेरिका विवाद में हमारे ब्राह्मण कहां से टपक गए? न जाने यह बंदा क्या खा-पीकर बात करता है ! खुद ट्रम्प भी बहक रहे हैं। वह भारत को 'डैड इकॉनमी' कह चुके हैं जबकि पहली तिमाही में हमने 7.8 फीसदी ग्रोथ दिखाई है। यह भी उस समय जब हम पर टैरिफ की तलवार लटक रही थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की सफल जापान यात्रा के दौरान जापान ने भारत में निवेश के टार्गेट को दो गुना बढ़ाते हुए 68 अरब डालर कर दिया है। ऐसा करते हुए जापान ने हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास प्रकट कर दिया है लेकिन ट्रम्प खफा है और बहुत खफा हैं,पागलपन की हद तक खफा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए ट्रम्प का यह भी कहना था, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं। आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ व्यापार या कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। क्या यह किसी मानसिक रूप से स्वस्थ राष्ट्राध्यक्ष की भाषा है? क्या किसी रणनीतिक साझेदार देश के प्रधानमंत्री को यह धमकी दी जा सकती है कि 'आपका सिर चकरा जाएगा'? ट्रम्प को रूसी तेल की चिन्ता नहीं। अलास्का में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का लाल गलीचा बिछा कर स्वागत किया था। हमारे साथ समस्या और है। हमने उनकी ईगो की मालिश करने से इंकार कर दिया। सारा यूरोप, जापान, कोरिया सब उनके आगे झुक गया। केवल भारत और ब्राज़ील अड़ गए। भारत ने उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का श्रेय देने से इंकार कर दिया जिससे ट्रम्प चिढ़ गए। अमेरिका में हमारी पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्ते को ट्रम्प की 'निजी चिढ़' बताया है। यही शब्द अमरीकी फाइनेंशल सर्विस कम्पनी जैफरीज ने भी कहे हैं। उनके अनुसार ट्रम्प की चिढ़ का कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ झगड़े में उन्हें मध्यस्थता नहीं करने दी। न्यूयार्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, राष्ट्रपति ट्रम्प ने बार-बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध 'हल' कर दियाजून 17 को नरेन्द्र मोदी के साथ टेलीफोन वार्ता में ट्रम्प ने यह बात फिर उठाई कि उन्हें कितना गर्व है कि उन्होंने युद्ध रुकवा दियाउन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल सम्मान के लिए मनोनीत करने जा रहा हैउनके कहने का एक प्रकार से अभिप्राय यह था कि मोदी भी ऐसा करें। उस 35 मिनट की लम्बा कॉल में मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सारे घटनाक्रम के दौरान न तो किसी भी स्तर पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बात हुई थी और न ही अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव ही आया था। इसी में इस बात का जवाब भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प को गुस्सा क्यों आता है? जैसे कोई बच्चा चाकलेट के लिए जिद करता है, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार खुद को नोबेल के सच्चे दावेदार कह रहे हैं। अगर हम तेल पर समझौता कर लेते तो फिर मांग यह होती कि हम रूस से हथियार लेना बंद कर दें क्योंकि 'इस पैसे से रूस यूक्रेन में युद्ध चला रहा है'। यह भी मांग हो सकती थी कि हम ब्रिक्स छोड़ दें और दूसरे देशों के साथ डालर के सिवाय दूसरी किसी मुद्रा में व्यापार करना बंद कर दें। अगर हम झुकते तो झुकते चले जाते। ईयू और जापान जैसे देशों ने रियायतें दी हैं, पर हमने स्पष्ट कर दिया कि कृषि, डेयरी और छोटे उद्योग जैसे क्षेत्र किसी के लिए खुले नहीं हैं। भारत में इंग्लैंड के पूर्व हाई कमिश्नर डॉमिनिक एसक्विथ का सही कहना है कि, कोई प्रमाण नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास संगत मांग है या समझौते का कोई रास्ता है। इसका कारण यही है कि मामला ट्रेड का इतना नहीं जितना अमेरिका के राष्ट्रपति की ईगो का है। उनके लिए मानना मुश्किल है कि भारत झुकने को तैयार नहीं। मैक्सिको के बारे ट्रम्प ने डींग मारी है कि 'वह करते हैं जो हम कहते हैं'। भारत मैक्सिको नहीं है। हम अमेरिका के साथ अच्छे सम्बन्धों की अहमियत को समझते हैं, पर हम निर्देश लेने को तैयार नहीं। एक साम्राज्यवादी ताकत को हटा कर दूसरी को अपने ऊपर लादने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ से कुछ सैक्टरों को धक्का जरूर पहुंचेगा, पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही निर्भर नहीं है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था का लगभग 90फीसदी निर्यात पर निर्भर है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का यह केवल 21-22फीसदी ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प अपने भक्तों को यह प्रभाव देना चाहते थे कि दुनिया के बड़े नेता उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। जैसे पहले बादशाह को नजराना चढ़ाया जाता था वैसा ट्रम्प अपने लिए चाहते हैं कि सब व्हाइट हाउस के दरबार में सलाम बजाएं। पर जबरदस्त दबाव के बावजूद यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन एक इंच नहीं हिले। चीन ने भी आंखें दिखाई तो ट्रम्प पीछे हट गए। सारी भड़ास हम पर निकाली जा रही है जो उल्टी पड़ गई है। ऐसी ही स्थिति हमने बंगलादेश युद्ध के समय देखी थी जब इंदिरा गांधी ने निक्सन के आगे झुकने से इंकार कर दिया था। 1998 में परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, पर भारत झेल गया। उसी नीति पर अब प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। हमने ट्रम्प को बता दिया कि हम तुम्हारी धुन पर नाचने के लिए तैयार नहीं हैं। सीएनएन पर एक विश्लेषक ने कहा है, अमेरिका ने भारत को खो दिया। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इस बीच चीन के तिआनजिन शहर में एससीओ की बैठक में 20 देशों के नेता मौजूद रहे। चीन दुनिया में खुद को वैकल्पिक लीडर पेश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की बेवकूफी ने चीन को और भी बड़ी ताकत बना दिया है। पहलगाम हमले के चार महीने के बाद ही मोदी की चीन यात्रा असामान्य है। शी जिनपिंग ने जरूर कहा कि 'हम पार्टनर हैं विरोधी नहीं', पर उनकी बात पर भारत में शायद ही कोई विश्वास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का वर्णन किया और घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निन्दा की गई है। यह हमारी कूटनीतिक विजय है क्योंकि अभी तक चीन पहलगाम का नाम लेने से कतरा रहा था। इस सम्मेलन से बड़ा संदेश यह है कि वर्ल्ड आडर हिल रहा है। प्रक्रिया तो पहले से शुरू है, पर ट्रम्प की विचित्र नीतियों के कारण इसमें तेजी आ गई है। उन्हीं की नीतियों के कारण भारत और चीन कुछ नजदीक आ रहे हैं। पर गर्मजोशी नहीं है। गलवान का टकराव भूलना मुश्किल है, पर कूटनीति एक जगह ठहर नहीं सकती। समय के साथ उसे बदलना है। भारत ने भी बता दिया है कि उसके पास भी विकल्प है। हमने रूस से तेल लेना बंद करने से भी इंकार कर दिया है। भारत की नीति का प्रभाव नजर आने लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो ट्रम्प की गुर्राने वाली टीम के प्रमुख सदस्य हैं, ने मोदी-पुतिन वार्ता से कुछ मिनट पहले सुर बदलते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता 'नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। और यह रिश्ता21वीं सदी को परिभाषित करेगा। हमारे लोगों को जंजीरों में वापिस भेजने के बाद रूबियो ने हमारे दो लोगों के बीच चिरस्थायी दोस्ती की बात कही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत के मूल्य चीन से कहीं ज्यादा हमारे साथ मेल खाते हैं। यह बात अब क्यों समझ आ रही है? दुनिया में दो खेमे हैं, अमेरिका-पश्चिम तो दूसरी तरफ चीन-रूस। पलड़ा उसका भारी रहेगा जिस तरफ भारत जाएगा। इसीलिए अनर्गल बयानबाजी से रिश्ते को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही है। पर भारत का इतिहास है कि हम खेमाबाजी से ऊपर हैं। हम अमेरिका को छोड़ नहीं रहे, न ही छोड़ सकते हैं। उनके साथ कई स्तर पर मजबूत रिश्ता है। रक्षा संबंध तगड़े हैं, वह हमारी सबसे बड़ी निर्यात मार्केट है और जो आज ड्रैगन और हाथी के टैंगो की बात कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि कम से कम अमेरिका हमारी सीमा पर तो नहीं बैठा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नाजुक समय में अमेरिका की बागडोर ट्रम्प जैसे अस्थिर आदमी के हाथ में है इसीलिए यह संदेश भेजना जरूरी था कि हम मैक्सिको या पाकिस्तान नहीं हैं। हम किसी के भी आधीन नहीं रहने वाले। चीन के खेमे में जाने का सवाल ही नहीं। रूस के साथ पुरानी दोस्ती चलेगी। पर हाल का घटनाक्रम यह जरूर बता गया है कि ट्रम्प की अजीबोगरीब नीतियों और हरकतों के कारण अमेरिका की ताकत और प्रभाव का तेजी से ह्रास हो रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/30882)

उमर खालिद की बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कपिल सिब्बल, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का किया जिक्र

नई दिल्ली ।

दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिब्बल ने इसे 'अन्याय' करार दिया है। क्योंकि बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों को जमानत देते ने इनकार कर दिया था। सिब्बल ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करना संविधान के अनुछेद 21 का उल्लंघन है। सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सही काम करने और इसके लिए आवाज उठाने से कतराते हैं। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज खामोश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, जब राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों को उठाने से बचते हैं, यह सोचकर कि इससे उनकी राजनीति को नुकसान हो सकता है। सिब्बल ने

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के उस कथित बयान पर भी निशाना साधा है।

जिसमें उन्होंने कहा था कि खालिद के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कम से कम सात बार सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केवल दो बार स्थगन मांगा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े एक यूएपीए मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने नौ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं, जबकि न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने तसलीम अहमद की याचिका खारिज की। दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने नौ जुलाई को आदेश सुरक्षित रखने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया। विस्तृत आदेश का इंतजार है। आरोपियों को 2020 से जेल में रखा गया है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत से जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि यह पूर्व-नियोजित और सुविचारित साजिश का मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी और केवल लंबी अवधि तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता। उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में 2022 से लंबित थीं।

दिल्ली बाढ़ पर मंत्री का बयान, जलमग्न होने की बात सही नहीं, बेवजह दहशत फैलाई जा रही

नई दिल्ली ।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके का निरीक्षण किया और कहा कि पूरे इलाके में पानी की एक बूँद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे हालात को इस तरह पेश करना ठीक नहीं है जैसे राष्ट्रीय राजधानी यमुना नदी में डूब गई हो।

वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में हो रही भारी बारिश के बीच नागरिकों में बेवजह दहशत फैलाई जा रही है।

पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सिविल लाइंस इलाके में पानी की एक बूँद भी नहीं है। रिंग रोड से सटी सर्विस रोड सड़क के स्तर से 8 से 10 फीट नीचे है और बारिश का पानी पंप करके निकाला जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली यमुना नदी में डूब गई है। मंत्री ने आगे कहा कि वह स्थिति का आकलन करने के लिए दिल्ली के निगम बोध घाट का भी दौरा करेंगे। इससे पहले सुबह, लोहा पुल से ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाज़ार, वासुदेव घाट और आसपास के रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। वासुदेव घाट के आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई गईं। संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर मयूर विहार फेज-1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। शहर के लिए यमुना का चेतावनी चिह्न 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। लोगों को निकालने का काम 206 मीटर से शुरू होता है। भारी बारिश के कारण, बुधवार को यमुना का जलस्तर अब तक के उच्चतम स्तर 208.66 मीटर पर पहुँच गया था। दिल्ली के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को मध्यम बारिश के साथ सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे का अनुमान है।

दिल्ली शराब नीति मामला : पंजाब में बाढ़ का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मांगी पेशी से छूट

नई दिल्ली ।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई टल गई है. वहीं, कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में करेगा. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुरुवार को अदालत में पेश होने से राहत दे दी. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वे इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत और बचाव कार्यों में पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस आधार पर उनकी उपस्थिति से दोनों नेताओं को पेशी से छूट दे दी. दिल्ली की शराब नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया है. इस मामले में कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच एजेंसी शिकंजा कस चुकी है. जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया कि इस नीति में जानबूझकर कमियां डाली गईं, जिससे निजी लोगों को फायदा पहुंचा और आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली. जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक, यह रकम गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल की गई. केजरीवाल को ईडी ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था, जबकि सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त-सितंबर 2024 में दोनों को जमानत दी थी, लेकिन कोर्ट में ट्रायल जारी है. इस मामले की शुरुआत 2022 में हुई, जब दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ते हुए PMLA के तहत केस दर्ज किया. हालांकि, अब देखना होगा कि अक्टूबर में होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर अदालत क्या कुछ अहम आदेश देती है.

बाढ़ पीड़ितों से मिलकर केजरीवाल का छलका दर्द, बोले- खाने-पानी तक की दिक्कत, सरकार कहाँ है?

नई दिल्ली ।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क क्षेत्र का दौरा किया और गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम राहत शिविर में लोगों का हालचाल जानने आए हैं। वे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें समय पर खाना नहीं मिल रहा है, मच्छरों का प्रकोप है, लेकिन उनसे निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की समस्या है, हमें बताया गया कि कल ही टेंट लगाए गए थे, जबकि बारिश पहले से ही हो रही थी। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम समझ सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएँ करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि राहत शिविरों में लोगों को सभी सुविधाएँ प्रदान करें। दिल्ली में हर जगह जलभराव है, कई इलाकों में इसका मुख्य कारण समय पर गाद निकालने का काम न होना, नालों की सफाई न होना और कई इलाकों में सीवर का बैकफ्लो होना है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पीने का पानी

राहत शिविरों में खाने की व्यवस्था तक नहीं- अरविंद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाएं केंद्र सरकार- केजरीवाल

नहीं है। इसलिए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि लोगों को जितनी भी सुविधाएँ उपलब्ध हों, उपलब्ध कराई जाएँ... पूरा उत्तर भारत - जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसलिए, मैं केंद्र से आग्रह करता हूँ कि लोगों को यथासंभव राहत प्रदान की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने अफ़ग़ानिस्तान में आए भूकंप के बाद राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। यह अच्छी बात है, लेकिन केंद्र को उन सभी राज्यों को भी राहत प्रदान करनी चाहिए जो इस समय संकट में हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया। पिछले दो घंटों से जलस्तर स्थिर बना हुआ है, आज सुबह 8 और 9 बजे भी यही स्तर दर्ज किया गया। लगातार बारिश के बाद नदी लगातार खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है। शहर के लिए यमुना का चेतावनी चिह्न 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। लोगों को 206 मीटर से निकालने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर था। हालाँकि, राजधानी में नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट के बावजूद, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच, दिल्ली जलभराव और संभावित बाढ़ के संकेतों से जूझ रही है। आज सुबह-सुबह लोहा पुल और आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त दृश्यों में यमुना नदी का विस्तार दिखाई दिया, जो भारी और निरंतर वर्षा के बाद कहर बरपा रही है।

जनता को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता- कैबिनेट मंत्री

पानीपत।

सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिला सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों का निवारण करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार न्याय को लेकर हमेशा गम्भीर रही है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी शिकायतें पहुंचती है उनको गम्भीरता से सुनकर प्रशासन के सहयोग से समाधान किया जाता है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतों में से सुनवाई करते हुए मंत्री ने 8 शिकायतों का मौके पर निदान किया व 5 अन्य शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा। उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि वे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को लेकर हमेशा गम्भीर रहे हैं व उनका प्रयास रहा है कि न्याय में किसी भी तरह की कौताही ना बरती जाए। उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया और पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह ने जिला सचिवालय पहुंचने पर मंत्री का बुके देकर स्वागत किया। जिला कष्ट निवारण समिति की इस बैठक में 13 शिकायतों में से 10 शिकायतें पुरानी थी व 3 शिकायतें नई थी, इनमें 9 शिकायतें पुलिस विभाग से सम्बंधित थी। मंत्री ने सुनवाई करते हुए पहली शिकायत रणबीर सिंह वासी अनाज

मण्डी समालखा की जिला अग्रणी बैंक अधिकारियों से सम्बंधित थी। यह पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसे सुनवाई के बाद आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा गया। दूसरी शिकायत पवन कुमार बीपीएल फलैट धारक द्वारा दी गई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। मंत्री ने एफआईआर करने के आदेश दिए व पुलिस विभाग को इस शिकायत को लेकर गम्भीरतपूर्वक कार्य करने के लिए कहा। मंत्री द्वारा इसका निष्तारण किया गया। तीसरी शिकायत रविन्द्र वासी झटीपुर द्वारा रखी गई थी। यह भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी, जिसमें मंत्री ने सुनवाई करते हुए इसका मौके पर निष्तारण किया। चौथी शिकायत रविन्द्र कुमार वासी सैक्टर - 12 पानीपत ने की थी। यह शिकायत पुलिस विभाग से सम्बंधित थी। शिकायतकर्ता ने दोषीगणों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के तहत न्याय दिलवाने की मांग रखी गई थी। यह भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसे जनसुनवाई के बाद आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा गया। पांचवी शिकायत गुलशन वासी पार्शवनाथ पॉलीवाल सिटी द्वारा दी गई थी। यह भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसमें शिकायतकर्ता ने मंत्री को अवगत करवाया कि वहां बिजली, पानी व सीवर की कोई सुविधा नही है और ना ही लाईनें बिछाई गई है जिसके चलते मकानों का निर्माण नही कर सकते। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने इसका मौके पर निष्तारण किया। छठी शिकायत प्रतीक माटा वासी पानीपत द्वारा दी गई।

यह भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसका सम्बंध भी पुलिस विभाग से रहा। इसमें शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी होने का आरोप लगाया था। इस पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने शिकायत का निष्तारण किया। सातवीं शिकायत बबीता वासी भीम गोडा मन्दिर

सनौली ने अपने पति के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी लेकिन वे इसको लेकर संतोष नही थी। इसे सुनवाई के बाद आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा गया। यह समस्या पुलिस विभाग से सम्बंधित थी। आठवी शिकायत राजकुमार वासी बाल जाटान ने रखी थी। इसमें लैण्डलूजर वाहन को स्थाई तौर पर लगवाने का अनुरोध किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने जनसुनवाई करते हुए दिसम्बर माह तक उनके वाहन को लगाने के निर्देश दिए। नौवी शिकायत ऊशा शर्मा वासी पानीपत द्वारा दी गई। यह शिकायत भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सम्बंधित थी। इसका भी मौके पर सुनवाई के बाद निष्तारण किया गया। शिकायत नम्बर 10 जोकि यूनिक बंसल वासी सैक्टर - 17 द्वारा दी गई थी। यह शिकायत जमीन मामले से सम्बंधित थी। यह शिकायत भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसको सुनवाई के बाद आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा गया। शिकायत नम्बर 11 सतीश वासी आट्टा द्वारा दी गई। यह शिकायत नई शिकायत थी जो यूएचबीवीएन विभाग से सम्बंधित थी। इस शिकायत की सुनवाई करते हुए इसका निष्तारण किया गया। शिकायत नम्बर 12 हरदीप संधु वासी हुड्डा ने पुलिस से सम्बंधित की थी। शिकायत में दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई थी। इसका सुनवाई करने के बाद निष्तारण किया गया। यह शिकायत नई शिकायत थी। शिकायत नम्बर 13 राम सिंह वासी मनाना द्वारा दी गई थी। यह भी नई शिकायत थी। इसमें लड़की पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर लड़की के पिता रामसिंह ने अपनी स्थिति स्पष्ट की व पुलिस पर मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया था। पुलिस विभाग ने इसमें निष्पक्ष जांच की बात कही थी। इसे भी आगामी बैठक के लिए लम्बित रखा गया। इस मौके पर भाजपा जिला

मंत्री ने कहा जिला कष्ट निवारण समिति बैठक में आने वाली हर समस्या का होगा निष्तारण

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 8 शिकायतों का मौके पर किया निष्तारण, 5 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए रखा गया लम्बित

उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने मंत्री का जिला सचिवालय पहुंचने पर बुके देकर किया स्वागत

अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, सांसद प्रतिनिधि गजेन्द्र सलुजा, उपायुक्त डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया, पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह, निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी, पानीपत एसडीएम मनदीप सिंह, इसराना एसडीएम नवदीप नैन, समालखा एसडीएम अमित कुमार, एमडी शुगर मिल संदीप कुमार, जिला परिषद सीईओ डॉ. किरण, नगराधीश टिनू पोशवाल, निगम संयुक्त-आयुक्त डॉ. संजय के अलावा जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य और सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मोदी सरकार के जीएसटी से मिलेगी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत- पीयूष गोयल

नई दिल्ली।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उसने नागरिकों पर भारी करों का बोझ डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जीएसटी में हालिया बदलाव से निवेश और रोजगार की एक नई लहर पैदा होगी जो भारत के विकास चक्र को गति देगी। नई दिल्ली में भाजपा द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्री ने तर्क दिया कि नई व्यवस्था के तहत कम करों से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव जो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, शायद आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया है। इतनी बड़ी राहत देश के उपभोक्ताओं को दी गई है, जो व्यापार करने में आसानी के लिए प्रभावशाली रहेगी। एक नई उमंग के साथ हमारे देश के

पीयूष गोयल का दावा- कांग्रेस ने लादा था भारी कर बोझ

किसान, युवा, महिलाएं, स्वस्थ और हर वर्ग का उपभोक्ता, उपभोक्ता, सभी को एक बड़ा तोहफा 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया था कि अब देश निकल पड़ा है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब बड़े परिणाम देने वाले कदम उठाने की क्षमता भारत में है। उन्होंने कहा कि 2014 में, जब

हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब यह क्षमता नहीं थी। हम सब जानते हैं कि उस समय अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी और सिर्फ भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। वादे तो हुए, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कभी एकीकृत कर प्रणाली की कल्पना की थी। लेकिन जब यूपीए सरकार आई, तो वे बिना कोई कार्रवाई किए वादे करते रहे।

राज्य सरकारों को उन पर भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के कारण ही जीएसटी एक वास्तविकता बन पाया।

गोयल ने कहा कि ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के अलावा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए। वादे बहुत किए जाते थे, लेकिन कार्रवाई गायब था। उन्होंने कहा कि 2017 से 2024-25 तक समय-समय पर जहां-जहां संभव हुआ प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में तो 100-150 आइटम्स पर एक साथ कम किए गए थे। देश के उपभोक्ताओं को लाभ देने का ये सिलसिला लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलता रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप लगाए और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन, आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के समय जो बोझ पेपर वर्क और टैक्स का था, वो 2017 में लक्ष्य आने के बाद लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए काल के उस दौर को याद कीजिए, जब लोगों पर उत्पाद शुल्क, वैट, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर के रूप में 30% से ज्यादा कर का बोझ था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। इससे न केवल करों में कमी आई है, बल्कि जीएसटी दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यापार करने में और आसानी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नकारात्मक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है।

वैष्णो देवी यात्रा 11वें दिन भी बंद, कटरा में पसरा सन्नाटा, श्रद्धालु मायूस

नई दिल्ली।

खराब मौसम और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 11वें दिन भी स्थगित है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकूटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा मार्ग असुरक्षित हो गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को अगली सूचना तक अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है, क्योंकि मरम्मत कार्य और सुरक्षा निरीक्षण अभी भी जारी हैं। यात्रा स्थगित होने के कारण कटरा आधार शिविर भी वीरान सा दिख रहा है और दुकानों और होटलों में भी लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है।

महमूद मदनी का दावा, पहलगाम आतंकी साजिश को नागरिक समाज ने रोका, वरना फैल जाती अराजकता

नई दिल्ली।

पहलगाम आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने का श्रेय देश के नागरिक समाज को देते हुए, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने शुक्रवार को कहा कि अगर यह घटना किसी और देश में होती, तो बहुत अराजकता फैल जाती। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, मदनी ने कहा कि देश का नागरिक समाज पहलगाम आतंकी हमले के पीछे की साजिश को समझता है, जिसका उद्देश्य देश में समुदायों के बीच फूट डालना था। उन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी उपलब्धि माना। मदनी ने कहा कि सबसे पहले, जिस तरह से उन बदमाशों ने दूसरों के नाम पूछकर उन्हें मार डाला - मैं अपने देशवासियों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जिन्हें मैं हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना

चाहता। उन्होंने धैर्य दिखाया। यह सच है - अगर यह कोई और देश होता, तो कौन जानता है कि किस तरह की अराजकता फैल जाती। यही भारत की खूबसूरती है।

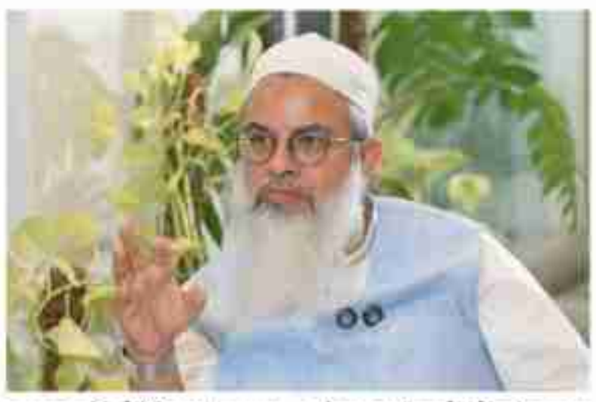

उन्होंने आगे कहा कि उस शर्मनाक घटना को नाकाम करने में सबसे बड़ी भूमिका इस देश के नागरिक समाज की थी। उन्होंने समझा कि यह इस देश में रहने वाले समुदायों को लड़ाने की एक साजिश है और इसे नाकाम कर दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना नागरिकों का कर्तव्य है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष ने भी यही किया। मदनी ने आगे कहा, -जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो अच्छे कामों के लिए भी सरकार की आलोचना करने वालों ने भी इसका समर्थन किया। अपनी सेना के साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटक मारे गए थे। इस हमले के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को तड़के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा संचालित आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए। भारत ने भी पाकिस्तान की बढ़ती आक्रामकता को नाकाम कर दिया और उसके हवाई ठिकानों पर बमबारी की। इससे पहले 28 जुलाई को, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया था।

तेजस्वी का दावा: भाजपा का बिहार बंद सुपर फ्लॉप, गुंडागर्दी कर के भी एक वार्ड बंद नहीं करा पाए

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार बंद के विरोध प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने बिहार में दुनिया भर से गुंडागर्दी फैलाई। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, यादव ने कहा कि बिहार बंद के लिए, वे रैली की तरह ही लोगों को काम पर रख सकते थे। जैसे वे रैलियों में पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, वैसे ही बंद के लिए, वे खुद पुलिस से यातायात रोकने के लिए कह सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने कल बिहार में दुनिया भर से गुंडागर्दी फैलाई। तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा के गुंडों ने खुलेआम महिलाओं और शिक्षिकाओं को पीटा, गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्राओं के साथ बदसलूकी की, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस रोकी और शहीदों के परिवारों को पीटा। उन्होंने आगे कहा, फिर भी ये निकम्मे लोग एक वार्ड तो दूर, एक पंचायत भी बंद नहीं करा पाए! शर्म आनी चाहिए इन पर! इन सब भाजपा की गुंडागर्दी को कवर न करने के लिए मीडिया पर हमला बोलते हुए, यादव ने कहा, चापलूस मीडिया भाजपा की गुंडागर्दी पर घबरा गया। बेचारे इस पर कोई बहस ही नहीं करते। विपक्ष के बंद में अगर एक छींक भी आ जाए, तो इनके स्टूडियो में जातिवादी तूफान आ जाता, इनकी पत्रकारिता पर मोर नाचने लगते, लेकिन बेचारे भाजपा की नाकामी से सदमे में हैं। इससे पहले, गुरुवार को तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने गुंडागर्दी की कोशिश की। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा और एनडीए का बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। उन्हें अपने बंद के लिए बिहार में किसी का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने केवल गुंडागर्दी करने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और एम्बुलेंस रोकीं। राजद प्रमुख लालू यादव ने भी राज्यव्यापी बंद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और पार्टी कार्यकर्ताओं पर राज्य की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, लालू यादव ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सदस्यों को बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आदेश दिया था।

अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, यमुना का जलस्तर घटा, पर खतरा अभी भी बाकी

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, खतरा अभी भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है और बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है। यमुना अभी भी अपने खतरे के निशान 205.33 मीटर से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। इसी वजह से नदी के किनारे बसी कॉलोनियों और निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है।

यमुना का जलस्तर - राहत और चिंता

अच्छी खबर यह है कि कई दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद, गुरुवार को यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हुआ। पुराने रेलवे पुल पर जो जलस्तर

207.48 मीटर तक पहुंच गया था, वह शुक्रवार सुबह 8 बजे तक घटकर 207.31 मीटर पर आ गया। लेकिन, यह कमी बहुत धीमी है और आगामी बारिश इसे फिर से बढ़ा सकती है।

इन इलाकों में अभी भी है पानी

यमुना से लगे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली से लेकर पूर्वी दिल्ली तक की झुग्गियों के लोग सड़कों पर आ गए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा, निगम बोध घाट, मनिस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबे हुए हैं, और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव चल रही है।

अगले 5 दिनों का मौसम- बारिश का अलर्ट

बाढ़ का पानी इन इलाकों तक पहुंच गया है
* मयूर विहार फेज-1
* रिंग रोड
* बुराड़ी
* अलीपुर
* यमुना बाजार
* सिविल लाइन्स
* दिल्ली सचिवालय

मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने दिल्लीवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी संभव है, लेकिन अचानक तेज बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं।

8 लाख के चालान पर भड़के अखिलेश यादव

लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की गाड़ी का चालान हुआ है. वो भी आठ लाख रुपये. इससे अखिलेश यादव जमकर भड़के. खूब सरकार को खरी-खोटी सुनाई. टोंटी चोरी के आरोप को याद करते हुए कहा कि इसे कभी नहीं भूल सकते. उन अधिकारियों का भी नाम लिया, जिन्होंने उनके सीएम आवास से जाने के बाद उस घर को गंगा जल से धुलवाया. अखिलेश यादव ने खुद बताया कि कल मुझे मेरी गाड़ी का चालान मिला. सरकार ने चालान किया है तो हमने कहा कि जो चालान है, वो भर दो. जब चालान देखा तो पता चला पूरे काफिले के चालान के लिए मुझे आठ लाख रुपये का चालान भरना है. जो सीसीटीवी कैमरा चला रहा है, वो बीजेपी का आदमी होगा. अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि शिक्षा और छात्र कैसे बर्बाद हों, सरकार इसपर काम कर रही है. ये सरकार नहीं चाहती कि पढ़-लिखकर कोई

सरकार से सवाल करे, इसलिए ये किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते. एबीवीपी के मामले में देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में आंदोलन होना चाहिए. एबीवीपी का मतलब अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई बन गया है. शैक्षणिक संस्थान बिना मान्यता के संस्थान चलाकर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं. सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करेगी, फिर बर्बाद करेगी. केतकी सिंह को अगर अपनी बेटी की चिंता है तो दूसरों की बेटी की भी चिंता करनी चाहिए. आप मुझपर टोंटी चोरी का आरोप लगाकर सीएम आवास को गंगाजल से धुलवायेंगे तो ये मैं भूल नहीं सकता. ये अवनीश अवस्थी और अभिषेक कौशिक का खेल था. हम टोंटी चोरी के आरोप भूल नहीं सकते, ये बात सरकार जान ले. अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी के प्रदर्शन पर कहा कि इसपर इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे कहे को भी वो बेच लेंगे. मैं जन्माष्टमी से सरकार की उल्टी गिनती गिन रहा हूं. आज से कुल 493 दिन सरकार के पास बचे हैं. पंचायत चुनाव और विधानसभा में वोट चोरी ना हो, इसके लिए हमारा संगठन लगातार जमीन पर काम कर रहा है. वोट चोरी का उदाहरण देखना हो तो कुंदरकी को देखिए, कुंदरकी में 77 प्रतिशत वोट सत्ता पक्ष को कैसे मिल सकता है? चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है. चुनाव आयोग ही विपक्ष को धोखा दे तो हम क्या करें? चुनाव आयोग बीजेपी को ऐसा कोड दे देता है, जिससे उन्हें घर बैठे वोट कराने तक का अधिकार मिल जाता है. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चुनाव आयोग के एआई सर्वे पर अखिलेश यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत का एक वोट सरकार नहीं काट सकती. बीड़ी बनाने वाले करोड़ों मजदूरों को सरकार को विशेष मदद करनी चाहिए. चुनाव को देखते हुए जीएसटी कम किया गया है. जीएसटी भले घट जाए लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी.

यमुना की बाढ़ से तबाही का मंजर- मजनू का टीला जलमग्न, घर-दुकानें डूबी; दुकानदारों का छलका दर्द

नई दिल्ली।

यमुना का उफनता पानी इस सप्ताह उत्तर दिल्ली के मजनू का टीला की तंग गलियों में घुस आया, जिससे दर्जनों घर और दुकानें जलमग्न हो गईं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पानी के उतरने के बाद इलाके में गीली लकड़ियां, टूटी मशीनें और उफने हुए नालों के गंदे पानी की बदबू अहसास कराती है कि बहुत कुछ अब नए सिरे से शुरू करना होगा। नदी किनारे बसी इस तिब्बती कॉलोनी में आम दिनों में कैफे छात्रों से गुलजार रहते हैं, टैटू पार्लर की नियोन लाइट जलती है और किराए के कमरों में चलने वाले होम-स्पा व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को संघर्ष में बदल दिया है। बाढ़ ने रेस्टोरेंट से लेकर टैटू पार्लर, सैलून, होम-स्पा और परिधान दुकानों तक हर तरह के व्यवसाय को प्रभावित किया है।

दफ्तर में ही सोने को मजबूर हैं कई दुकान मालिक

कई दुकान मालिक अब अपने दफ्तर में ही सोने को मजबूर हैं, जबकि मशीनों के खराब हो जाने से सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। रेस्टोरेंट चलाने वाले जुंगी ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट के पीछे स्थित घर की छत तक पानी आ गया। ''पिछले 15 वर्षों से मेरा परिवार यह रेस्टोरेंट चला रहा है। हर बार जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है, हमारा घर डूब जाता है। इस बार तो सब कुछ... बिस्तर, फर्नीचर, कपड़े... सब पानी में चला गया। रेस्टोरेंट ऊपरी मंजिल पर है, इसलिए वह बच गया, लेकिन हमारा घर और सामान सब तबाह हो गया। कई दुकानदारों ने बताया कि उन्हें पास के होटलों में शरण लेनी पड़ी है। मजनू का टीला में करीब दो दशक से रह रहे लाबसांग सेरिंग ने बताया कि कई परिवार ऊंचे इलाकों में किराए के कमरों में रह रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी दुकानों के भीतर ही सो रहे हैं ताकि व्यवसाय से दूरी न हो। इलाके में संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मोबाइल नेटवर्क बाधित है और बिजली आपूर्ति भी अनियमित है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने स्टाफ के साथ समन्वय के लिए वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल शुरू किया है। जुंगी ने कहा ''फोन बंद रखते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए बैटरी बची रहे।

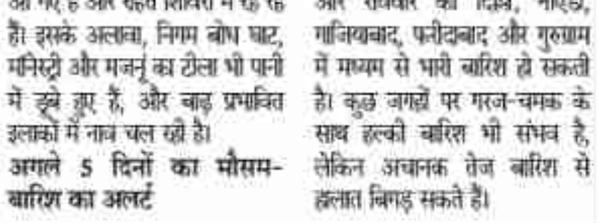

उपकरण नष्ट हो गए हैं...

कॉलोनी की निचली गलियों में चलने वाले व्यवसायों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक टैटू पार्लर के कर्मचारी ताशी ने कहा कि उनकी सभी मशीनें नष्ट हो गई हैं। ''हमारी मशीनें हमने जमीन में लगा रखी थीं और पूरा सेटअप पानी में डूब गया। इन मशीनों की कीमत लाखों में है। इनके बिना पार्लर नहीं चल सकता। एक अन्य टैटू पार्लर के मालिक डेविड ने बताया कि अधिकतर इंक और उपकरण नष्ट हो गए हैं। ''हम दो रातों के लिए होटल में रुके। यहां गलियां इतनी तंग हैं कि पानी तेजी से नहीं निकलता। वहीं, ठहर जाता है और मच्छरों व संक्रमण का खतरा पैदा करता है।

मशीनें- सब खराब हो गए हैं- दुकानदार

दुकानदारों का कहना है कि खराब सड़कों और कमजोर जल निकासी के कारण स्थिति और बिगड़ गई। जुंगी ने कहा ''सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सड़कें बहुत संकरी हैं और पानी जल्दी नहीं निकलता। सांप और मच्छर हालात को और खराब कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब जल्दी सामान्य हो जाए। होम-स्पा में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी भारी नुकसान की बात कही। अपने घर के बेसमेंट में स्पा केंद्र चलाने वाली 26 वर्षीय निमा ने कहा ''मसाज बेड, ड्रायर्स, स्टीम मशीनें- सब खराब हो गए हैं। ग्राहकों ने बुकिंग रद्द कर दी है और हमें नहीं पता कि काम कब दोबारा शुरू हो पाएगा। इलाके के होटल अब अस्थायी आश्रय बन गए हैं, जहां परिवार और कर्मचारी एक कमरे में साथ रह रहे हैं।

हर साल होता है नुकसान

मठ के पास स्थित एक होटल के कर्मचारी संदीप ने कहा ''हमारे होटल में पांच-छह कर्मचारी एक साथ रह रहे हैं। कुछ मालिकों ने किराया कम कर दिया ताकि लोग रुक सकें। बाढ़ ने दुकानों में काम करने वालों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है। एक गिफ्ट शॉप में काम करने वाली अनीशा ने बताया कि उन्होंने बच्चों को पैसे लेकर तैरते हुए बेसमेंट से सामान निकालते देखा। उन्होंने कहा ''यह खतरनाक है, लेकिन दुकानदार अपना स्टॉक बचाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नुकसान हर साल होता है। एक फूड स्टॉल चलाने वाले सेरिंग ने कहा कि अब पानी थोड़ा कम हुआ है लेकिन मरम्मत का खर्च काफी होगा। उन्होंने कहा ''अब हमें दीवारों की पुताई करानी होगी, फर्नीचर बदलना होगा और मशीनें ठीक करनी होंगी। यह हर साल ऐसा ही होता है।

मच्छर और सांप घरों में घुसने लगे हैं

सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दो बच्चों की मां वान्या ने बताया कि ठहरे हुए पानी के कारण मच्छर और सांप घरों में घुसने लगे हैं। उन्होंने कहा ''बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और हम उन्हें सुरक्षित रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आवारा जानवरों की हालत पर भी चिंता जताई। एक होटल के कर्मचारी राजेश ने बताया, ''यहां के आवारा कुत्ते पहले ही कमजोर थे। अब वे ऊंचाई वाले हिस्सों या छतों पर फंसे हैं। न खाना है, न पानी। रात भर भौंकते हैं। यह तकलीफदायक है। कई लोगों के लिए बाढ़ के बावजूद वहीं रहना मजबूरी है। एक कर्मचारी ने बताया, ''जिनके परिवार थे, वे आश्रय स्थलों की ओर चले गए, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रुके हैं। हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी दुकानें और रेस्टोरेंट यहीं हैं। अगर हम गए, तो घर और काम दोनों चले जाएंगे।

धीरेंद्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात, इस बार पर चिंतित दिखे बागेश्वर धाम के महंत

नई दिल्ली। दिल्ली में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी. साथ ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करते हुए वीडियो के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की. मुख्यमंत्री ने वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह शॉल ओढ़ाकर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने लिखा, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुख्यमंत्री जनसेवा सदन पधारे. स्नेहिल भेंट के लिए आभार. साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में बागेश्वर धाम के पूजनीय आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी का पावन आगमन हुआ. उनकी ऊर्जा समाज को सेवा, श्रद्धा और सनातन संस्कारों से जोड़ती है. जनसेवा के इस महायज्ञ में उनकी सहभागिता जनभावनाओं को और भी सशक्त बनाती है तथा हमें निरंतर यह प्रेरणा देती है कि -सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. इस मुलाकात के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संतों के बीच आपसी मतभेदों को लेकर भी अपनी बात रखी. भिवंडी के बागेश्वर सनातन मठ में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर संतों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि धर्म और समाज में संतों की भूमिका बहुत अहम है और किसी भी प्रकार का विवाद समाज में गलत संदेश देता है. इस पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सभी को शांति और समझदारी का संदेश दिया. धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मुद्दों का भी जिक्र किया. उन्होंने प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बीच विवाद को लेकर कहा कि प्रेमानंद महाराज ने पीढ़ी को भजन और साधना से जोड़ा, वहीं जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में बयान देकर राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान दिया. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ हुई भेंट और संतों के बीच आपसी सद्भाव की बात समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली है. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे विवादों से दूर रहें और धर्म, समाज व संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दें.